



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण 1939 (श10)
(सं0 पटना 660) पटना, मंगलवार, 25 जुलाई 2017

संख्या ब0-15/बी0एस0जी0-268/2014-815/वि0

वित्त विभाग

संकल्प

25 जुलाई 2017

विषय :- वर्ष 2016-17 में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु निवेदित दरों में निर्धारित न्यूनतम (L-1) दर पर आगे के तीन वर्षों यथा- 2018-19 से 2020-21 तक के बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण कर बजट पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ इन अवधियों के लिए, वर्ष 2016-17 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित न्यूनतम (L-1) दर पर सी.डी. (राइट कर) उपलब्ध कराने के लिए, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम, सर्वश्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2005 के नियम 131 ज़(ड) के तहत नामांकन आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में ।

संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्ति एवं व्यय का विवरण विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है जो “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहलाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण मुख्य बजट दस्तावेज होता है। इसके अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय विवरण के पूरक के रूप में कई अन्य प्रकार की बजट पुस्तिकाएं भी विधान मंडल में प्रस्तुत की जाती हैं, इसमें कई बजट पुस्तिकाएं को प्रस्तुत किया जाना राज्य सरकार का वैधानिक दायित्व भी है। इन

सभी बजट पुस्तिकाओं के अतिरिक्त सरकार की अर्थव्यवस्था एवं विकास को प्रदर्शित करने से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण नाम की पुस्तिका भी प्रत्येक वर्ष विधान मंडल में उपस्थापित की जाती है।

2. बजट से संबंधित सभी पुस्तिकाओं का मुद्रण अत्यंत गोपनीय ढंग से एवं तय समय सीमा के अन्दर कराकर विधान मंडल में उपस्थापित कराया जाना, राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय बजट पुस्तिकाओं को अंतिम रूप दिये जाने एवं उसे विधान मंडल में उपलब्ध कराने के बीच काफी कम समय ही उपलब्ध हो पाता है। दूसरी तरफ निविदा की प्रक्रिया अपनाये जाने में काफी समय व्यतीत होते हैं एवं इससे बजट निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में अनावश्यक विलम्ब होता है।

3. वर्ष 2017-18 की बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण, इस संबंध में प्रकाशित निविदा के आधार पर, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम, सर्वश्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, से करायी गयी है। इसी प्रकार बजट पुस्तिकाओं का सी.डी. राइट भी प्रत्येक वर्ष, इसके लिए प्राप्त किये गए कोटेशन के आधार पर क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2005 के नियम 131(ज़)(ख) के अन्तर्गत न्यूनतम (L-1) दर पर कराया जाता है। इस हेतु वर्ष 2017-18 के बजट पुस्तिका के मुद्रण हेतु निविदा आमंत्रण के विज्ञापन में अंकित शर्तों एवं विशिष्टताओं के अधीन - बजट भाषण पुस्तिका को छोड़कर अन्य बजट पुस्तिकाओं के एक सेट में अनुमानित टेक्स्ट पृष्ठों की संख्या (लगभग) 4500, कवर पेज की संख्या (लगभग) 59 तथा इसी प्रकार बजट भाषण पुस्तिका के एक सेट में अनुमानित टेक्स्ट पृष्ठों की संख्या (लगभग) 100 तथा कवर पेज की संख्या 01 अनुमानित की गयी थी। पृष्ठों की संख्या बढ़ने या घटने पर उसी अनुपात में मुद्रण मूल्य में वृद्धि या कमी की गणना का शर्त रखा गया था। इस आधार पर वर्ष 2017-18 के बजट पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु प्रति सेट कर सहित निर्धारित न्यूनतम(L-1) दर निम्नवत् है:-

Detail of L1 Rate Per set Budget	Rate in Rs.
For one set of Budget Book's text pages (on one colour on 80 gsm paper)	1845.00
For one set of Budget Book's cover pages (in bi-colour on 300 gsm Art board)	203.00
For one set of Budget Book's (other than Budget Speech) Total Rate	2048.00
For one set of Budget speech's text pages (in one colour on 130 gsm Art paper)	59.00
For one set of Budget Speech Book's cover page (in four colour on 300 gsm Art board)	4.95
For one set of Budget Speech Book's Total Rate	63.95

तथा वर्ष 2017-18 के सी0डी0 राइट का प्रति सी0डी0 न्यूनतम(L-1) दर कर सहित 39/- है।

4. उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य का बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम, सर्वश्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, द्वारा किया जाता रहा है। ये प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष, निविदा के सभी शर्तों का पालन करते हुए, न्यूनतम (L-1) दर

पर मुद्रण का कार्य अतिगोपनीय ढंग से एवं समयबद्ध तरीके से तय समय सीमा के अंदर करते हुए वित्त विभाग को, बजट पुस्तिकाएँ सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराते आ रहे हैं ।

5. वर्ष 2016-17 में, वर्ष 2017-18 के बजट पुस्तिकाओं के मुद्रण के लिए न्यूनतम(L-1) दर पर वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के लिए बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण कराने एवं इससे संबंधित सी.डी. राईट कराने पर राज्य सरकार पर अलग से कोई अतिरिक्त वित्तीय भार उत्पन्न नहीं होगी, इस संबंध में सर्वश्री सरस्वती प्रेस लि०, कोलकाता द्वारा भी लिखित रूप से सहमति व्यक्त की गई है। इसके साथ-साथ बजट निर्माण के समय निविदा/पुनर्निविदा की प्रक्रियात्मक जटिलताओं में लगने वाले समय की भी बचत होगी और विधान मंडल में बजट पुस्तिकाओं का उपस्थापन ससमय करने में सुविधा होगी। साथ ही साथ बजट पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु इस क्षेत्र में विगत कई वर्षों से अनुभव प्राप्त सफल प्रतिष्ठान की सेवा राज्य सरकार को प्राप्त होती रहेगी ।

उपर्युक्त परिस्थिति में, उक्त कंडिका-3 के अनुरूप वर्ष 2016-17 में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु निवेदित दरों में निर्धारित न्यूनतम(L-1) दर पर आगे के तीन वर्षों यथा-2018-19 से 2020-21 तक के बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण कर बजट पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ इन अवधियों के लिए, वर्ष 2016-17 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित न्यूनतम (L-1) दर पर सी.डी. (राईट कर) उपलब्ध कराने के लिए, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम, सर्वश्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2005 के नियम 131 झ(ड) के तहत नामांकन आधार पर प्राधिकृत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक-18.07.2017 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या संख्या 15 के रूप में, नीतिगत निर्णय लेते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एच० आर० श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 660-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>